जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 46 संख्याः 302 प्रभात बीकानेर, रविवार 25 मई, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

थरूर विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा, कांग्रेस का केरल में

विवाद की जड़, पीढ़ी परिवर्तन भी लगती है

- पुरानी पीढ़ी के नेता थरूर के वक्तव्यों को, पार्टी के परम्परागत, ''कमांड स्ट्रक्चर'' को चुनौती मानते हैं और पार्टी की एकता को चुनौती करार देते हैं।
- पर, नई पीढ़ी के नेता थरूर के आकर्षण को एक ''एसैट'' (ताकत) मानते हैं।
- केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष के. सुधाकरण का मत है, ''कांग्रेस के हाईकमान ने गलती की, थरूर का नाम अपनी लिस्ट में नहीं दिया, जो उन्होंने सरकार को सौंपी थी, पार्टी के प्रतिनिधि के चयन के लिए। थरूर ने सदा देश के हित को ध्यान में रखकर काम किया है। अतः उनका नाम नहीं देना, थरूर के साथ अन्याय था।
- दूसरी ओर केरल कांग्रेस के अधिकांश परम्परावादी नेता मानते हैं कि थरूर का बार-बार मोदी व उनकी नीतियों की बढ़ाई करना, पार्टी के भाजपा के विरूद्ध एक ''युनाइटेड फ्रंट'' पेश करने के प्लान को कमज़ोर करता है।
- एक वरिष्ठ नेता, अपना नाम न देने की शर्त पर बोले कि बिहार के चुनाव की दृष्टि से बनाई गई पार्टी की रणनीति का आधार, मोदी की छवि को चुनौती देना है। विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब मोदी ऑपरेशन सिंदूर को चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाना चाहते हैं।
- मोदी बार-बार राहुल गांधी का मखौल बनाते हैं, केन्द्रीय सरकार के ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने की वजह से। इस मौके पर थरूर का सरकार की नीति से जुड़ना, भाजपा के हाथों में खेलना है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 मई। भारत-पाक सीमा पर तनाव फिलहाल के लिए स्थिर नज़र आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर द्वारा मोदी सरकार के एक आउटरीच मिशन के निमंत्रण को तुरंत स्वीकार किए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी में एक राजनीतिक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ है। थरूर के इस कदम से पार्टी में उनके भविष्य को लेकर अटकलें शुरु हो गई हैं, खासकर केरल और दिल्ली में, जहाँ यह चर्चा जोरों पर है कि वे केन्द्र की भाजपा सरकार के साथ किसी संभावित समीकरण की दिशा में बढ़ रहे हैं।

तथापि, थरूर के समर्थक उनके बचाव में उतर आए हैं। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष के. सुधाकरन ने सार्वजनिक रूप से थरूर का समर्थन किया और थरूर का नाम पार्टी प्रतिनिधियों की आधिकारिक सूची से हटाने को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना की। सुधाकरन ने कहा, ''थरूर ने हमेशा राष्ट्रीय हित में काम किया है और उन्हें दरकिनार करना अन्यायपूर्ण है।'' उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी को ऐसे नेताओं को अलग-थलग नहीं करना चाहिए, जिनके पास जन समर्थन और अंतरराष्ट्रीय पहचान है।

इस मामले ने कांग्रेस की केरल इकाई के भीतर बढ़ती फूट को उजागर किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी. डी. सतीसन ने टिप्पणी करते हुए कहा, ''यह मामला पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। आंतरिक मतभेदों को सही मंचों पर हल करना आवश्यक है।''

पार्टी के भीतर के सूत्रों का कहना है कि केरल में कांग्रेस के एक बड़े वर्ग को थरूर द्वारा बार-बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों की सार्वजनिक सराहना से नाराजगी है। उनका मानना है कि इस तरह की गतिविधियाँ भाजपा के खिलाफ कांग्रेस की एकजुट रणनीति को कमज़ोर करती हैं। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने, नाम न

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग से दुष्कर्म : दो अभियुक्तों को 20 साल की सजा

जयपुर, 24 मई। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग किशोरी से तीन साल के अन्दर दुष्कर्म करने वाले दो अभियुक्त दीपक और जगदीश को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि एक अभियुक्त ने पीड़िता से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती किया और दूसरा उससे तीन साल पहले दुष्कर्म कर चुका था। यौन अपराध का बाल मन पर गहरा असर होता है। ऐसे

- पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने सांभर लेक के मामले में निर्णय सुनाया।

में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 12 फरवरी, 2022 को सांभर लेक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसके 17.5 साल की बेटी पिछले कुछ माह से गुमसुम रहने लगी और उसका शरीर भी भारी लग रहा था। इसके साथ ही वह बार-बार उल्टियां भी कर रही थी। ऐसे में उसने अपनी भाभी के जरिए पुछवाया तो पीड़िता ने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। पीड़िता ने कहा कि करीब तीन साल पहले जब वह पशु चरा रही थी तो जगदीश ने उसके साथ दुष्कर्म

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हार्वर्ड युनिवर्सिटी को अस्थायी राहत मिली

अन्य देशों के विद्यार्थियों को एडमिशन न देने के ट्रम्प के आदेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा

- अब, युनिवर्सिटी व अन्य देशों के लगभग सात हजार विद्यार्थी, जो हार्वर्ड में पढ़ रहे थे या रिसर्च कर रहे थे, को तुरन्त वापस नहीं जाना पड़ेगा। इनमें 700 विद्यार्थी भारतीय हैं।
- हार्वर्ड में कई दशकों से कैंसर पर रिसर्च चल रही है तथा मरीज़ों के मूत्र व खून के ''सैंपल'' प्रिज़र्व करके रखे गये हैं। ये सैंपल इस बीमारी पर रिसर्च करने के लिये अमूल्य निधि हैं। पर, इनको अशुद्ध न होने के लिये करोड़ों रूपए खर्च होते हैं।
- पर, अब हार्वर्ड की ''फण्डिंग'' कम कर देने से इन ''सैंपल'' का प्रिज़र्वेशन खतरे में पड़ जायेगा, जो मानव जाति के लिये असहनीय नुकसान होगा।
- दशकों पुराने इन सैंपल्स की कमी अब बहुत खलेगी, क्योंकि आधुनिक साधनों, जैसे ए.आई. से अब मौका मिला है मानव जाति के लिए अबूझ पहेली बनी, बीमारियों पर और गहराई से रिसर्च करने का।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 मई। अंतरराष्ट्रीय छात्रों को शैक्षिणक पाठ्यक्रमों में दाखिला देने पर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से हार्वर्ड विश्वविद्यालय को अस्थायी राहत मिल गई है। यह खबर वर्तमान वर्ष के लगभग 7,000 छात्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो हार्वर्ड के विभिन्न कोर्सों में पढ़ रहे हैं। इनमें लगभग 700 छात्र भारतीय हैं, जो अपने छात्र वीज़ा खोने और देश लौटने की आशंका से जूझ रहे थे।

हालांकि विश्वविद्यालय और इसके अध्यक्ष के लिए यह एक तरह की जीत है, लेकिन युनिवर्सिटी और विदेशी छात्रों के लिए भविष्य की अनिश्चितता बरकरार है। संकेत मिल रहे हैं कि नए शैक्षिणक सत्र के लिए दाखिलों की संख्या में भारी गिरावट आई है।

चिंता यह भी है कि फिलहाल यह प्रयास विफल होने के बावजूद, ट्रंप प्रशासन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए फिर से कोई नया आदेश ला सकता है। छात्र समुदाय का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई के बाद हार्वर्ड या अन्य अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जारी रखना कठिन हो सकता है।

कई छात्र हैरान और परेशान हैं कि हार्वर्ड में दाखिला लेना, जो जीवन भर का सपना होता है, शायद अब पूरा न हो पाए।

दाखिलों के अलावा, ट्रंप प्रशासन द्वारा शीर्ष अमेरिकी विश्वविद्यालयों के विरूद्ध उठाए गए अन्य कदम विज्ञान और वैज्ञानिक शोध परियोजनाओं के लिए बड़ा झटका साबित हो सकते हैं। इससे कुछ बुनियादी अनुसंधानों और विज्ञान के भविष्य को नुकसान होगा।

पूरी मानवता के लिए बेहद अहम एक अध्ययन दांव पर है। हार्वर्ड

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दोनों देशों ने ऑपरेशन पहलगाम के मुख्य ''नायकों'' को सम्मानित किया

पाकिस्तान ने जनरल असीम मुनीर को ''फील्ड मार्शल'' बनाया। भारत ने आईबी चीफ को एक साल का ''एक्सटैंशन'' दिया

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 24 मई। युद्ध मानवता के लिए सदैव नुकसानदायक ही रहा है। भारत और पाकिस्तान - दोनों ही पहलगाम हमले के बाद चार दिन चले संघर्ष में अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं।

इस बीच, आई बी चीफ तपन डेका को मोदी सरकार ने 1 वर्ष का सेवा-विस्तार (एक्स्टेन्शन) दे दिया है, जबकि कुछ लोग उन पर पहलगाम-नरसंहार में खुफिया तंत्र की असफलता का दोषारोपण कर रहे हैं। उन्हें एक्स्टेन्शन का यह पुरस्कार दूसरी बार दिया गया है और इस प्रकार वे इंटेलिजेंस ब्यूरो (आई बी) के सबसे ज्यादा लम्बे समय तक रहने वाले निदेशक बन गये हैं।

उधर, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई पाकिस्तान की शर्मनाक स्थिति के बाद, जनरल आसिम मुनीर को पदोन्नत कर दिया है। जिन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए था, वे पदोन्नत कर दिये गये हैं।

डेका के एक्स्टेन्शन के लिए सिफारिश करने वाले लोग बार-बार यह कहते रहे हैं कि तपन कुमार डेका क्रॉस-बॉर्डर टैररिज़्म के विशेषज्ञ हैं, उन्हें कश्मीर का लम्बा अनुभव है तथा पहलगाम आतंकी हमले के बाद की परिस्थिति में उनकी सेवाएं बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन डेका के आलोचकों का कहना है कि आतंकवाद के एक ऐसे विशेषज्ञ, जिन्हें कश्मीर के आतंकी स्थलों की गहन जानकारी एवं समझ है, के होते हुए पहलगाम में इतना घातक नरसंहार कैसे हो गया?

ये लोग यह आरोप भी लगा रहे हैं कि डेका उन 26 निर्दोष लोगों की मौतों के लिए सीधे जवाबदेह हैं, जिन्हें सीमा-पार के आतंकियों ने नृशंसतापूर्वक गोलियों से उड़ा दिया। ये हत्यारे जबरदस्त संरक्षित नियंत्रण रेखा को पार कर पाकिस्तान से भारत में आखिर घुस कैसे आये, यही नहीं, उन्होंने भारत-भूमि पर करीब 200 किलोमीटर की दूरी भी तय करली, और तपन डेका नामक इस तथाकथित सुपर स्पाई की सीधी देख-रेख में काम कर रहे दुर्जेय बल को उनके बारे में पता नहीं चला?

पहलगाम दुखान्तिका के एक महीने बाद भी, भारतीय जमीन पर मौजूद ये पाकिस्तानी आतंकी ढूढ़े नहीं जा सके हैं। क्या यह एक बहुत ही बड़े स्तर एवं आकार की लापरवाही, अक्षमता नहीं है, जिसकी कीमत 26 निर्दोष भारतीयों ने अपनी जान देकर चुकाई है?

गाँव को नगर पालिका की सीमा से बाहर करने का आदेश स्थगित

जयपुर, 24 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के गत 27 मार्च के उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसके तहत राजस्व ग्राम तोडिया का बास को बानसूर नगर पालिका की सीमा से बाहर किया गया था। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में प्रमुख स्वायत्त

- हाईकोर्ट में पेश याचिका के अनुसार नगर पालिका की सीमा में शामिल ग्राम को सीमा से बाहर करने की शक्ति नगर पालिका अधिनियम में नहीं है।

शासन सचिव, डीएलबी निदेशक, पंचायती राज सचिव, कोटपूतली-बहरोड़ कलेक्टर और नगर पालिका बानसूर सहित, अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनिल उपमन की एकलपीठ ने ये आदेश स्थानीय निवासी बंसी राम व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गांधी अस्पताल में भर्ती जे. एण्ड के. के पूर्व गवर्नर से मिलने गए

सतपाल मलिक 11 मई से अस्पताल में हैं तथा आजकल डायलिसिस पर चल रहे हैं

- राहुल गांधी ने कुछ देर सतपाल मलिक से बात की और कहा, सच के लिए लड़ाई में वे सतपाल मलिक के साथ हैं।
- 22 मई को सीबीआई ने तीन साल की जाँच-पड़ताल के बाद सतपाल मलिक के खिलाफ चार्जशीट पेश की न्यायालय में 2200 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले किरू हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट में सिविल काम का ठेका देने के मामले में।
- राहुल गांधी ने पुंछ में पाकिस्तान के आतंकी हमले में मरे तेरह जनों के परिवार से भी मुलाकात की। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा, वे राहुल गांधी को पहले ही बुलाना चाहते थे, पर, उन्हें आने की इजाज़त नहीं मिल पाई थी।

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 24 मई। कांग्रेस नेता तथा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल शाम जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की कुशल-क्षेम पूछने गये। ज्ञातव्य है कि मलिक काफी बीमार हैं तथा दिल्ली के आर एम एल अस्पताल में भर्ती हैं। आज सुबह राहुल गांधी जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में गये तथा इस महीने के शुरू में भारत-पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मिले।

कल शाम साढ़े पांच बजे राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाकर, राहुल गांधी ने मलिक की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली तथा उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों से चर्चा की। मलिक 11 मई को अस्पताल में भर्ती हुए थे तथा इस समय डायलसिस पर हैं।

गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''आज मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी से मिला तथा उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। आशा करता हूं कि वे शीघ्र ही ठीक हो जायेंगे। मैं सत्य की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ा हूं।''

सूत्रों ने कहा, ''मलिक आज चार दिन बाद होश में आये। वे आई सी यू में भर्ती हैं तथा राहुल ने कुछ मिनट उनसे बातचीत की।''

22 मई को सी बी आई ने मलिक तथा पांच अन्य के खिलाफ किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दिये गये 2200 करोड़ रु. के सिविल वर्क्स के ठेके में कथित अनियमितताओं को लेकर चार्जशीट पेश की। तीन साल तक की जांच-पड़ताल के बाद, एक विशेष अदालत में मलिक तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ यह चार्जशीट पेश की गई है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुबह जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में गये तथा वहां इस महीने के शुरू में भारत-पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित हुए परिवारों से मिले।

विदित ही है कि जम्मू-कश्मीर के पर्यटन केन्द्र पहलगाम के पास बैसारण में इस्लामाबाद समर्थित आतंकियों द्वारा पर्यटकों पर किये गये एक घातक हमले के बाद, भारत और पाकिस्तान बड़े और पूर्ण युद्ध के कगार पर पहुंच गये थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सेवारत कोटे से पीजी करने वालों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं

जयपुर, 24 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने सेवारत कोटे में मेडिकल पीजी डिप्लोमा कर रहे प्रार्थी का ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव और निदेशक, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जाम सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन ने ये आदेश डॉ. संजय

- हाईकोर्ट ने प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव तथा निदेशक नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम से जवाब मांगा।

शर्मा की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता ने इन सर्विस अभ्यर्थी के तौर पर साल 2023 में नीट पीजी परीक्षा दी थी। उसे मेरिट में आने पर काउंसलिंग के जरिए अक्टूबर 2023 में राजकीय सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'विकसित राजस्थान 2047 का विज़न डॉक्युमैंट तैयार हो रहा है'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने नीति आयोग में जल व ऊर्जा सुरक्षा के लिए अधिक सहयोग का अनुरोध किया

- मुख्यमंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए बैट्री स्टोरेज के लिए 5000 मेगावॉट आवर का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित करने तथा 40 गीगावॉट अतिरिक्त ऊर्जा के इवेक्युएशन हेतु प्लान तत्काल बनाने का अनुरोध किया।
- उन्होंने कहा कि पौंग बाध में पूर्ण क्षमता तक जल भराव के लिए शीघ्र निर्णय लिया जाये तथा 51.5 किलोमीटर लम्बी फिरोजपुर फीडर की लाइनिंग के लिए स्वीकृति प्रदान की जाये।

नई दिल्ली/जयपुर, 24 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को नई दिल्ली के भारतमंडपम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की दसवीं बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शर्मा ने बैठक में विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की विस्तार से चर्चा की और प्रदेश में जल और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार से अधिक सहयोग का भी अनुरोध किया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विकसित राजस्थान का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर पहलू पर तेजी से काम कर रही है। इसी दिशा में आर्थिक समृद्धि, सतत् विकास और समावेशी प्रगति को केन्द्र में रखते हुए नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 'विकसित राजस्थान 2047' विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने रामजल सेतु लिंक परियोजना तथा यमुना जल समझौते को मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जल परियोजनाएं विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगी।

मुख्यमंत्री ने बैठक में केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि पोंग बांध की कुल भराव क्षमता 1400 फीट ऊंचाई तक अनुमत है, लेकिन पर्याप्त वर्षा के दौरान भी इस बांध में अधिकतम सीमा तक जल भराव नहीं किया जा रहा है। पोंग बांध को पूर्ण क्षमता तक जल भराव करने के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाए, जिससे भागीदार राज्यों को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की दसवीं बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान से जुड़े मुद्दों और मांगों को रखा।

सायबर ठगी में बैंक खाता नहीं विवादित राशि फ्रीज़ करें

जयपुर, 24 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि साइबर ठगी के मामले में उपभोक्ता के पूरे बैंक खाते को फ्रीज करने के बजाए खाते में आई विवादित राशि को ही फ्रीज किया जाना चाहिए। इसके साथ, ही अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक को निर्देश दिए

- हाईकोर्ट ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को याचिकाकर्ता के बैंक खाते को डीफ्रीज़ करने के निर्देश दिये।

हैं कि वह याचिकाकर्ता के बैंक खाते को डीफ्रीज करे और सिर्फ खाते में आए विवादित 55,141 रुपए की फ्रीज करे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता जांच में बैंक और अनुसंधान अधिकारी का सहयोग करें। वहीं, जांच लंबित रहने के दौरान खाते को बंद भी नहीं किया जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)